भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1490
उत्तर देने की तारीख-09/02/2026

क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2025 में भारतीय विश्वविद्यालय

†1490. **श्री बैजयंत पांडा:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, 2025 में कुल कितने भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग की गई है;
(ख) उक्त रैंकिंग में अर्हता प्राप्त करने में विफलता के लिए जिम्मेदार विश्वविद्यालयों में इन कारकों में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और
(ग) क्या सरकार का वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुसंधान निधि का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स (क्यूएस एयूआर) में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) का प्रतिनिधित्व पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ है। वर्ष 2020 में जहाँ 100 संस्थान रैंक किए थे, वहीं यह संख्या लगातार बढ़कर वर्ष 2025 में 163 तक पहुँच गई। इसके अतिरिक्त, नवंबर 2025 में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 के नवीनतम संस्करण में भारतीय एचईआई की संख्या बढ़कर 294 हो गई है।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना की उपलब्धता, अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को

मजबूत करना, तथा उद्योग–अकादमिक संबंधों का संवर्धन शामिल है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित पहलें भी शामिल हैं।

i. केन्द्रीय वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रदान की जा रही बजटीय सहायता के अतिरिक्त, भारत सरकार उच्च शिक्षा में सुधार हेतु तीन प्रमुख घटकों नामतः - चयनित राज्य विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ाना ,विश्वविद्यालयों को अधोसंरचना अनुदान प्रदान करना,बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)/प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii. अकादमिक जगत, उद्योग और उद्यम निर्माण के अनुसंधान एवं विकास संचालित एकीकरण उद्देश्य से इन संस्थानों के आसपास अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए प्रमुख एचईआई में अनुसंधान पार्क स्थापित किए गए हैं। ये अनुसंधान पार्क उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देते हुए उद्योग से वित्तपोषित अनुसंधान को प्रदान करते हैं।

iii. भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु सरकार ने वर्ष 2018-19 में ₹1650 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो (पीएमआरएफ़) योजना शुरू की, जिसके लिए प्रावधान किया गया। एचईआई में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 6000 से अधिक एचईआई ने अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

iv. एनईपी 2020 के सिद्धांतों के अनुरूप, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ़) को प्राकृतिक विज्ञानों (जिसमें गणितीय विज्ञान भी शामिल हैं), अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च-स्तरीय कार्यनीति दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य

v. भारत सरकार ने सभी एचईआई और अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के छात्रों, संकाय सदस्यों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों की विद्वत पत्रिकाओं तक व्यापक पहुँच का विस्तार करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना को अनुमोदित किया है। इस योजना के अंतर्गत 6300 से अधिक संस्थान शामिल हैं। योजना के लिए 3 कैलेंडर वर्षों — 2025, 2026 और 2027 — के लिए कुल लगभग 6,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

vi. अंतर्विषयक अनुसंधान करने, अत्याधुनिक अनुप्रयोग विकसित करने और स्वास्थ्य, सतत शहरों तथा कृषि के तीन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर समाधान तैयार करने के लिए

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक कुल 990 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ स्वास्थ्य, सतत शहरों और कृषि प्रत्येक क्षेत्र में से एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने को अनुमोदित किया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक एआई उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) को आईआईटी मद्रास में 500 करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ संस्वीकृत दी गई है।

vii. तकनीकी बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना को 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक सहित 275 तकनीकी संस्थानों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) के अनुरूप पहलों को लागू करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता, समानता और सुशासन में सुधार करना है। वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए 4200 करोड़ रूपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ यह एक 'केंद्रीय क्षेत्र योजना' है।

उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग हेतु युगल, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश) विनियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। इन विनियमों का उद्देश्य भारतीय एचईआई को विदेशी एचईआई के साथ शैक्षणिक सहयोग में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

यूजीसी ने भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 को भी अधिसूचित किया है ताकि भारतीय छात्रों को किफ़ायती लागत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके और भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाया जा सके। यूजीसी ने ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी एचईआई को बेंगलुरु (कर्नाटक), दिल्ली एनसीआर, मुंबई (महाराष्ट्र) और चेन्नई (तमिलनाडु) सहित पूरे भारत में परिसर स्थापित करने के लिए 14 आशय पत्र (एलओएल) जारी किए हैं।

भारतीय एचईआई के विदेशी परिसरों अर्थात ज़ांज़ीबार में आईआईटी मद्रास का परिसर, आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का परिसर, तथा दुबई में आईआईएम अहमदाबाद के परिसर भी स्थापित किए गए हैं।

*****